दादरा और नगर हवेली एवं दमण-दीव के विलय का लोकसभा से पास हुआ विधेयक

■ विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर और दमण-दीव के सांसद लालू पटेल ने विधेयक का समर्थन करते हुए विधानसभा के गठन की भी मांग की ■ दोनों के एक केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद इसकी लोकसभा में दो सीटें होंगी, बॉम्बे हाईकोर्ट पहले की तरह यहां के विधिक मामले देखेगा

(असली आजादी न्यूज नेटवर्क) नई दिल्ली 27 नवंबर। लोकसभा ने बुधवार को दो केंद्रशासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का विलय कर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। पिछले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने क्षेत्र के जनजाति समुदाय के लोगों के आरक्षण को लेकर सदस्यों की आशंकाओं पर स्पष्ट किया कि संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण वैसे ही मिलता रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। जी. किशन रेड्डी ने कहा कि दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाने का उद्देश्य उनकी प्रशासनिक सुगमता को बढ़ाना तथा विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि एक केंद्रशासित प्रदेश बनने से अधिकारी सप्ताह के पांचों कार्यदिवस पर उपलब्ध होंगे जो अभी दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग दिन उपलब्ध रहते हैं। रेड्डी ने साफ किया कि लोकसभा सीटों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल के कुछ संशोधनों को अस्वीकृत करते हुए दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक 2019 को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान की। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए दोनों केंद्रशासित क्षेत्र के लोकसभा सदस्यों ने केंद्र सरकार से यहां विधानसभा का गठन करने की भी मांग की। दादरा और नगर हवेली के निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी सरकार से अपेक्षा है कि दोनों क्षेत्रों की संस्कृति और परपराओं में बदलाव नहीं होना चाहिए। यहां जनजातीय समुदाय का आरक्षण भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि दोनों केंद्रशासित क्षेत्रों में विधानसभा का गठन होना चाहिए। दमण और दीव के भाजपा सांसद लालू पटेल ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए क्षेत्र में दिल्ली और पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा के गठन की मांग की। कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने दोनों केंद्रशासित क्षेत्रों के विलय की जरूरत पर सवाल किया। चर्चा में केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल (राकांपा), तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और वाईएसआर कांग्रेस के एन रेड्डेप्पा ने भी भाग लिया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की नीति के तहत दोनों संघ राज्यक्षेत्रों की कम जनसंख्या और सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर विचार करते हुए दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों का एक संघ राज्यक्षेत्र में विलय करने का निश्चय किया गया और इसलिए यह विधेयक लाया गया है। इसमें कहा गया है कि दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के विलय के लक्ष्य दक्षता बढ़ाकर और कागजी कार्यों में कमी लाकर दोनों संघ राज्यक्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, प्रशासनिक व्यय में कमी लाना, नीतियों और योजनाओं में एकरूपता लाना, योजनाओं की बेहतर निगरानी करना तथा विभिन्न कर्मचारियों के काडर का बेहतर प्रबंधन करना आदि हैं। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि दमण एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र की प्रशासनिक संरचना, इतिहास, भाषा और संस्कृति एक जैसी हैं। दोनों संघ राज्यक्षेत्रों के विभिन्न विभागों के सचिव, पुलिस प्रमुख, वन संरक्षक सामान्य हैं और गृह मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी उनके कार्य आवंटन के अनुसार इन दोनों राज्यों में सेवाएं देते हैं। इसके अलावा दो सचिवालय और दो समांतर विभाग हैं। दादरा और नगर हवेली में सिर्फ एक जिला है जबकि दमण और दीव में दो जिले हैं। विधेयक में कहा गया है कि दो संघ राज्यक्षेत्र में दो पृथक संवैधानिक और प्रशासनिक सत्ता होने के कारण कार्य में दोहराव होता है, कार्य क्षमता में कमी आती है और फिजूलखर्ची बढ़ती है जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार आता है। यह देखते हुए इस विधेयक को लाया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे के अधिकांश प्रावधानों को पांच अगस्त को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वर्तमान में देश में नौ केंद्रशासित प्रदेश हैं। दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली के विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर आठ हो जाएगी।

दोनों संघ प्रदेशों के विलय विधेयक का समर्थन करते हुए सांसद मोहन डेलकर ने विधानसभा की रखी मांग

■ आदिवासियों के आरक्षण यथावत रखने की मांग करते हुए दोनों संघ प्रदेशों के संबंध, व्यवहार एवं रीति-रिवाजों से सांसद मोहन डेलकर ने संसद को कराया अवगत

(असली आजादी न्यूज नेटवर्क) नई दिल्ली। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी सरकार से अपेक्षा है कि दोनों क्षेत्रों की संस्कृति और परपराओं में बदलाव नहीं होना चाहिए। यहां जनजातीय समुदाय का आरक्षण भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दोनों संघ प्रदेशों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर जो इच्छाशक्ति एवं उद्देश्य दिखाया गया है वह खुशी की बात है। मोहन डेलकर ने इस बिल पर दोनों संघ प्रदेश पर कोई विपरित असर न हो इसके लिए खास ध्यान आकर्षित कराया। जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों के लोगों का वर्षों से मधुर संबंध बना आ रहा है इसकी रक्षा होनी चाहिए। आदिवासी आरक्षण तथा सुविधाएं देना काम किया जा रहा है यह खुशी बात है। मोहन डेलकर ने दादरा नगर हवेली के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। जिसमें उन्होंने बताया कि 1954 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद 1961 में हम भारत का हिस्सा बने। सांसद मोहन डेलकर ने संसद में दोनों केंद्रशासित क्षेत्रों में विधानसभा के गठन की मांग भी की। उन्होंने कहा कि दोनों संघ प्रदेशों को वर्षों से विधानसभा के गठन की मांग की जा रही है। विधानसभा के महत्व का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने वर्ष 2014 में लोकसभा की स्टेंडिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि हाल के उपराष्ट्रपति एवं तत्कालिन स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में बनी गृहमंत्रालय की स्टेंडिंग कमेटी ने दोनों संघ प्रदेशों का दौरा करके जनसंख्या के आधार पर एवं पुडुचेरी के तर्ज पर यहां विधानसभा का गठन हो सकता है ऐसी रिपोर्ट तैयार किया था जो राज्यसभा में स्टेबल हुई है।

दमण-दीव सांसद लालू पटेल ने विलय का किया समर्थन: विधानसभा गठन की उठाई आवाज

(असली आजादी न्यूज नेटवर्क) नई दिल्ली। दमण-दीव के सांसद लालू पटेल ने विधेयक का समर्थन करते हुए क्षेत्र में दिल्ली और पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा के गठन की मांग की। सांसद लालू पटेल ने कहा कि हम इसका स्वागत करते है। दोनों संघ प्रदेशों का विलय होने से समानता आयेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास और मजबूत होगा। सांसद लालू पटेल ने कहा कि दोनों संघ प्रदेशों के एक हो जाने से सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में पांच दिन उपलब्ध होंगे। संघ प्रदेश में ग्रुप-बी एवं सी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका देना का सांसद लालू पटेल ने मुद्दा उठाया। कई सालों से डेलीवेजिस पर काम कर रहे लोगों को नियमित करने, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के सरपंचों को अधिकार देने सहित का भी मुद्दा संसद में रखा। सांसद लालू पटेल ने दिल्ली एवं पुडुचेरी के तर्ज पर मिनी असेम्बली देने की भी मांग की।

दोनों संघ प्रदेशों के विलय के ऐतिहासिक बिल के समर्थन के लिए सिलवासा नगरपालिका अध्यक्ष राकेशसिंह चौहाण ने दोनों सांसदों का माना आभार

(असली आजादी न्यूज नेटवर्क) सिलवासा। दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली को विलय करके एक संघ प्रदेश बनाने के लिए आज लोकसभा में विधेयक पास हुआ। इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने के लिए दमण-दीव सांसद लालू पटेल एवं दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर का सिलवासा नगरपालिका अध्यक्ष राकेशसिंह चौहाण ने आभार व्यक्त किया है। राकेशसिंह चौहाण ने कहा है कि संघ प्रदेश दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली का विलय करके दादरा नगर हवेली एवं दमण-दीव एक संघ प्रदेश बनाया जा रहा है। इसके लिए आज लोकसभा में विधेयक पास हुआ। इस विधेयक को समर्थन देने के लिए दोनों सांसदों को धन्यवाद देता हूं।

दोनों संघ प्रदेशों के विलय का समर्थन करने के लिए दोनों सांसदों को प्रदेश भाजपा ने दिया धन्यवाद

(असली आजादी न्यूज नेटवर्क) दमण। दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली को विलय करके एक संघ प्रदेश बनाने के लिए आज लोकसभा में विधेयक पास हुआ। इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने के लिए दमण-दीव प्रदेश भाजपा ने दमण-दीव सांसद लालू पटेल एवं दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता माजीद लधानी ने बयान जारी कर रहा है कि आज लोकसभा में ऐतिहासिक दिन था। दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली दोनों संघ प्रदेशों का विलीनीकरण का प्रस्तावित बिल दादर नगर हवेली एंड दमण-दीव मर्जर एक्ट-2019 ध्वनि मत से लोकसभा में पारित हुआ। आज सदन में इस ऐतिहासिक बिल को दानह के सांसद मोहन डेलकर और दमण-दीव के सांसद लालू पटेल ने अपना भरपूर समर्थन दिया एवं स्वागत किया। इसके लिए हम दमण-दीव प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोनों सांसदों का आभार व्यक्त करते है और धन्यवाद देते है।